achieve the target of tourist arrivals laid down by the Department.

Delhi Airport-Lacks Facilities.

5666. SHRI GHULAM MOHD. KHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact the Delhi Airport lacks facilities and arrangements for passengers and congestion, people waiting in the cold outside the airport, no toilet facilities, costly eating places, no public address system, absence of information about flight schedule and indifferent and unhelpful staff all these are common there; and

(b) the steps taken by Goverment to improve the situation ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : (a) and (b) No, Sir. Delhi Airport has been provided with the requisite facilities for passengers. Visitors are allowed entry into the terminal building on payment of the prescribed fee. Adequate provision exists for Flight Information and Public Address System, snack bars and restaurants, toilets etc. The airport staff are available to the passengers and visitors for their assistance.

During peak-hours, the terminal building is sometimes congested due to bunching of flights. To overcome this problem, a new International Terminal Building with a capacity to handle 3.3 million passengers per annum is under construction and will be commissioned in 1985. As an interim measure, it has also been decided to shift the international departures from the main Terminal Building to the Interim Departure Building.

सीमा सड़क महानिदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश में जौलजिवी अस्कोट मुंस्यारी मोटर सड़क का निर्माण

5667. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क महानिदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही जौल-जिवी अस्कोट-मुंस्यारी मोटर सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इस वर्ष इस पर कितनी धन राशि खर्च किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सड़क का निर्माण कार्य समय पर पूरा होने की संभावना नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस सड़क के निर्माण कार्य मे तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) मूल योजना के अनुसार इस सड़क की मार्च, 1985 तक बन कर पूरी हो जाने की संभावना थी। पर्याप्त निधि उपलब्ध न होने के कारण, भूमि अर्जन में विलम्ब तथा वन-संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने में देरी होने की वजह से निर्माण कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। यह आशा की जाती है कि यह सड़क 1986 के अन्त तक बना कर पूरी कर ली जाएगी। वर्ष 1983 84 के दौरान इस सड़क के लिए आबटित व्यय 66 लाख रुपये है।